इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 4 अंक सं. : 2 सितम्बर 2011

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूाी

मुख्य घटनाएं--- 1
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां---2
बैंकिंग ागत की घटनाएं--3
विनियामकों के कथन ---4
विदेशी मुद्रा --5
बीमा ------------------------------------ --------------------------------6
नयी नियुक्तियां---6
उत्पाद एवं गंठजोड---6
अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक--6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं ---7
शब्दावली ---7
संस्थान समाचार--7
बाज़ार की खबरें---8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएं

कारबार संपर्कियों द्वारा मोबाइल भुगतान सेवा क्षेत्र में प्रवेश

मोबाइल धनराशि के लिए आपाधापी अब बैंकों के लिए कारबार संपर्कियों के रूप में कार्य करने वाली फर्मों की रुचि का क्षेत्र बन गई है। ये संस्थाएं ग्रामीण केन्द्रों में वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में बैंकों की सहायता करती हैं। वर्ष 2015 तक भारत में 350 बिलियन अमरीकी डालर के भुगतानों और बैंकिंग लेनदेनों के सेल फोनों के माध्यम से होने की आशा के परिणामस्वरूप इनमें से कई एक कम्पनियां अब स्वयं अपनी मोबाइल लेनदेन सेवाएं आरंभ करने की प्रक्रिया से गुजर रही हैं। बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप (BCG) के अनुसार देश के दूर-दराज वाले भागों में बैंक शाखाएं खोलने की तुलना में मोबाइल प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए बैंकिंग और भुगतान सेवाएं प्रदान करना काफी कम खर्चीला है। "भारत में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान अपने शैशव काल में हैं। आज, भुगतानों की अपेक्षा स्वचालित टेलर मशीनों के माध्यम से आहरणों का हिस्सा समस्त कार्ड लेनदेनों के 90% से अधिक है।"

बैंक शाखाएं नकली नोटों का बेहतर पता लगाती हैं

बैंकों में उन्नत जागरूकता और नोट छंटाई मशीनों (NSMs) के बढ़े हुए उपयोग के कारण वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान पकड़े गए नकली बैंकनोट परिमाण की दृष्टि से पिछले वर्ष के 401,476 नगों की तुलना में 435,607 नगों के रूप में अधिक थे। पकड़े गए नकली नोटों के लगभग 90% (अर्थात् 390,372 नग) का पता बैंक शाखाओं में लगा, जो नोट छंटाई मशीनों (NSMs) के बढ़े हुए उपयोग का संकेत है। अप्रैल, 2011 में बैंकों ने 50 लाख रुपये और उससे अधिक की औसत दैनिक नकदी प्राप्तियों वाली शाखाओं में 4,091 नोट छंटाई मशीनें (NSMs) संस्थापित कर रखी थीं। इसके अलावा, उन्होंने 1,823 और शाखाओं में मशीन द्वारा संसाधित नोट जारी किए जाने की व्यवस्था कर रखी थी। बैंकों द्वारा नोट छंटाई मशीनों (NSMs) के उपयोग में तेजी लाए जाने के परिणामस्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक के स्तर पर नकली नोटों का पता लगाने का स्तर पिछले वर्ष के 52,620 से घट कर 45,253 नग ही रह गया।

बैंक नवम्बर 2011 में लिपिकीय कर्मचारियों के लिए साझी परीक्षा हेतु तैयार

लिपकीय पदों के लिए 19 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की अब तक की पहली साझी लिखित परीक्षा (CWE) बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) द्वारा इस वर्ष नवम्बर माह में संचालित की जाएगी । उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की शुरूआत 25 अगस्त 2011 से हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थियों को अपने आपको 25 सिम्बर, 2011 से पहले पंजीकृत करा लेना होगा। किसी अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों (जो एक वर्ष तक वैध रहेंगे) का उपयोग बैंकों द्वारा यथा समय घोषित किए जाने वाले रिक्त पदों को भरते समय किया जाएगा। उनके लिए सहभागी बैंकों में नौकरियों के लिए पुन: किसी लिखित परीक्षा में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी, अपितु उनके अंक के आधार पर उन्हें साक्षात्कार / व्यक्तित्व की जांच के लिए सीधे बुलाया जाएगा।

सूक्ष्म वित्त संस्थाएं गरीबी मिटाने में सहायक

सूक्ष्म -ऋण सम्मेलन अभियान की एक रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (MFIs) ने पिछले दो दशकों में लगभग 9 मिलियन परिवारों को ऋण प्रदान करते हुए गरीबी पर काबू पाने में उनकी सहायता की है। सूक्ष्म वित्त से जुड़े लगभग 45 मिलियन पारिवारिक सदस्यों को अपनी दैनिक आमदनी में 1990-2010 के बीच 1.25 अमरीकी डालर के प्रारंभिक स्तर से अधिक की वृद्धि परिलक्षित हुई।

कारबार संपर्कियों को प्रशिक्षित करें - भारतीय रिज़र्व बैंक

जहां बैंकों द्वारा कारबार संपर्की मॉडल के माध्यम से वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों के अधिकाधिक रूप से कार्यान्वयन की शुरूआत हो गई है, वहीं भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव ने इस बात पर बल दिया है कि बैंकों को अपने कारबार संपर्कियों को उनके द्वारा बैंक रहित क्षेत्रों में दायित्व संभाले जाने से पहले प्रशिक्षित करना चाहिए। "पर्याप्त प्रशिक्षण के बिना अधिकांश कारबार संपर्की स्थानीय लोगों का विश्वास अर्जित करने में सफल नहीं होंगे। बैंकों द्वारा यह प्रशिक्षण इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स (IIBF) जैसी संस्थाओं के माध्यम से प्रदान किया ाा सकता है और उसकी लागत बैंकों और नाबार्ड द्वारा वहन की ाा सकती है।" इस प्रकार के प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम शुल्क प्रति व्यक्ति 4,000 रुपये होने का अनुमान है और नाबार्ड उक्त संस्था द्वारा साालित की ााने वाली एक विशेष योाना के तहत इस शुल्क के 75%-100% का पुनर्वित्तीयन कर सकता है।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक ने व्युत्पन्नियों की बिक्री के मानदंड संशोधित किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्युत्पन्नी उत्पाद प्रदान करने वालों की तुलना में बैंकों को अधिक सुरक्षित एवं ग्राहकोनुकूल बनाने के लिए अपने मानदंडों को आशोधित कर दिया है। अब बैंकों के अनुपालन अधिकारी के लिए अपने निदेशक मंडल को यह प्रमाणित करते हुए एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि बैंक द्वारा किए गए व्युत्पन्नियों के सभी लेनदेनों के मामले में सभी आशोधित दिशानिर्देशों का पालन किया गया है। नये दिशानिर्देशों के अनुसार भारत में परिचालनरत विदेशी बैंक उनमें उत्पादों का मूल्य-निर्धारण भारत में स्थानीय स्तर पर करने का सामर्थ्य होने पर केवल विशिष्ट उत्पादों के मामले में गौण बाज़ार के प्रमुख सक्रिय सदस्य (market maker) हो सकते हैं। कोई भी ऐसा बैंक किसी ऐसे उत्पाद के मामले में गौण बाज़ार का प्रमुख सक्रिय सदस्य (market maker) नहीं हो सकता, जिसका मूल्य-निर्धारण वह स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता। ग्राहकों को व्युत्पन्नी उत्पाद उपलब्ध कराने से पहले बैंकों को कम्पनी के निदेशक बोर्ड से सम्बन्धित अधिकारी को उस कम्पनी की ओर से व्युत्पन्नियों का लेनदेन करने हेतु प्राधिकृत किए जाने का अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए।

अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए चलनिधि समायोजन सुविधा का समय परिवर्तित

भारतीय रिज़र्व बैंक 16 अगस्त से प्रत्यावर्ती पुनर्खरीद (reverse repo) की नीलामियों का संचालन शनिवार को छोड़कर कामकाज के सभी दिवसों को सायं 4.30 बजे और 5.00 बजे के बीच कर रहा है। इस मुहिम से उस अस्थिरता को रोकने में सहायता प्राप्त होगी, जो मई में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी दूसरी चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) को बंद कर दिए जाने के बाद एक दिवसीय मुद्रा बाज़ार में आ गई थी। बैंक अधिशेष निधियों को अभिनियोजित करने या फिर उधार सम्बन्धी किसी अवश्यकता को पूरी करने के लिए मुद्रा बाज़ार की ओर रुख किया करते थे, जिसके परिणामस्वरूप एक दिवसीय मांग दरों और संपार्श्वीकृत उधार एवं उधारदायी दायित्वों में असामान्य वृद्धि या कमी हो जाया करती थी। वर्तमान में चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत पुनर्खरीद और प्रत्यावर्ती पुनर्खरीद नीलामियां प्रात: 9.30 और 10.30 बजे के बीच आयोजित की जाती हैं। चलनिधि समायोजन सुविधा परिचालनों के सम्बन्ध में दीपक मोहन्ती पैनल के अनुसार पुनर्खरीद और प्रत्यावर्ती पुनर्खरीद खिड़की एक दिन में केवल एक बार ही खुलती है।

वित्तीय समावेशन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के परिचालनात्मक दिशानिर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कम मूल्य वाले खातों को सेवा प्रदान करने और अल्प सुविधा प्राप्त कम आय वाले क्षेत्रों को बैंकिंग की मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक अंतरण प्रणाली कार्यान्वित करने हेतु परिचालनात्मक दिशानिर्देश जारी किए हैं। विनियामक ने बैंकों से गावों में '

एक जिला - कई बैंक - एक अग्रणी बैंक' मॉडल अपनाने के लिए कहा है, जिसके द्वारा वित्तीय समावेशन योजना के तहत अभिहित बैंक और निधि अंतरण प्रणाली भिन्न होंगे। राज्य सरकार भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय और राज्य स्तरीय बैंकर समिति के परामर्श से अग्रणी बैंक अभिहित करेगी। अग्रणी बैंक राज्य सरकार से निधियां प्राप्त करेगा और इन निधियों को अंतरबैंक अंतरण के माध्यम से अन्य बैंकों को अंतरित करेगा।

बैंकों से नकदी के समक्ष 50,000 रुपये से अधिक के मांग ड्राफ्ट जारी न करने हेतु कहा गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को नकदी जमा के समक्ष 50,000 रुपये और उससे अधिक के मांग ड्राफ्ट जारी न करने की चेतावनी दी है। शीर्ष बैंक ने यह चेतावनी दी है कि "इन अनुदेशों के किसी प्रकार के उल्लंघन पर गंभीर रुख अपनाया जाएगा।" उसने यह भी कहा है कि "वित्तीय प्रणाली और विशेष रूप से बैंकिंग चैनलों की ईमानदारी परम महत्व रखती है। इसप्रकार, व्यापक श्रेणी वाले प्रशाखनों को देखते हुए इन दिशानिर्देशों के किसी प्रकार के उल्लंघन को गंभीर वि नियामक चिंता का विषय माना जाएगा।" भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह विनिर्णय दिया है कि बैंकों द्वारा 50,000 रुपये और उससे अधिक के मांग ड्राफ्ट, डाक अंतरणं, तार अंतरण और यात्री चेक ग्राहक के खाते को नामे करके या फिर खरीदार द्वारा दिए गए चेकों या अन्य लिखतों के समक्ष जारी किए जाने चाहिए और नकद भुगतान के समक्ष नहीं। यह सोने, चांदी और हीरे (प्लै टिनम) की खुदरा बिक्री पर भी लागू होता है।

ग्राहक सेवा बेहतर बनाएं : बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक के पैनल का निर्देश

गृह ऋणों को बदलने अथवा विफल एटीएम लेनदेनों के बाद धनराशि वसूल करने के लिए संघर्ष करने हेतु प्रभार का भुगतान करने वाले बैंक के ग्राहकों को न्यूनतम शेष राशि न रखने के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए। बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राहक सेवा पर भारतीय प्र तिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री एम. दामोदरन की अध्यक्षता वाली एक स मिति ने भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंकिंग प्रथाओं में भारी परिवर्तनों का सुझाव दिया है। इनमें सभी बैंकों के लिए एक ऐसे शुल्क रहित काल सेंटर के नंबर का समावेश है, जिस पर कोई ग्राहक फोन कर सके और उसके बाद उसे सम्बन्धित बैंक को परिवर्तित किया जा सके। जमा पक्ष में उक्त पैनल ने इस बात पर बल दिया है कि सभी बैंकों को न्यूनतम शेष राशि निर्धारित किए ि बना तथा ग्राहक की लिखित सहमति के बिना जमा खातों को स्वत: नवीकृत किए बिना चेक सु विधा, एटीएम कार्ड आदि जैसी कुछेक सुविधाओं सहित सादे बचत खातों की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। जमाराशियों के लिए बीमा सुरक्षा को इस समय 1,00,000 रुपये से बढ़ा कर 5,00,000 रुपये कने का भी सुझाव दिया गया है।

पुराने, नये उधारकर्ताओं के लिए एकसमान दरें

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बेर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री एम. दामोदरन की अध्यक्षता वाली उपर्युक्त समिति ने कहा है कि "अस्थिर ब्याज दर वाले परिदृश्य में जब उधारकर्ताओं की समस्त श्रेणी एक ही प्रकार की विशेषताओं और जोखिम स्तर वाली हो, तो (पुराने और नये) ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाने वाली ब्याज दर में उनके आने के समय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।" उक्त पैनल का यह भी कहना है कि बैंकों को अन्य बैंकों एवं वित्तीय कम्पनियों के पास जाने की सुविधा प्रदान करने के लिए गृह ऋणों के मोचन निषेध के रूप में मनमाने दंडात्मक ब्याज नहीं लगाना चाहिए। " यह सुनिश्चित करने हेतु एक नीति बनाई जानी चाहिए कि किसी ग्राहक को बाज़ार की प्रतियोगिता द्वारा प्रदत्त लाभ उठाने के लिए अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं के पास जाने जैसे विकल्पों का प्रयोग करते हुए उसके आर्थिक कल्याण को बढ़ाने से वंचित न रखा जाए।"

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से 1 सितम्बर से केवल इलेक्ट्रॉनिक भुगतान

केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने अब सरकार द्वारा स्वाधिकृत सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वे केवल इलेक्ट्रॉनिक विधि से ही भुगतान करें। इस मुहिम का उद्देश्य चेकों के माध्यम से निधियों के अंतरण में भ्रष्टाचार को रोकना और सम्पूर्ण प्रक्रिया को पारदर्शी एवं द्रुत गति वाली बनाना है। 1 सितम्बर से 35 में से किसी भी बैंक द्वारा चेक से कोई भुगतान नहीं स्वीकार किया जा रहा है । मंत्रालय बीमा कम्पनियों से भी उनके सभी आदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के प्रसार क्षेत्र को लागू करने के लिए कह रहा है। अपनी ई-अभिशासन से सम्बन्धित पहलकदमी के एक अंग के रूप में मंत्रालय ने इन निकायों से कागज़ र हित निधि अंतरण का मार्ग अपनाने के लिए कहा है, ताकि कर्मचारियों, विक्रेताओं, ग्राहकों तथा सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं को चेकों के माध्यम से भुगतानों में अनियमितताओं को रोका जा सके।

भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रस्ताव से इक्विटियों पर उधार प्रभावित हो सकते हैं

बैंकों के भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ऋण जोखिम के लिए आंतरिक श्रेणी निर्धारण आधारित (IRB) दृष्टिकोण के सम्बन्ध में उनके प्रारूप दस्तावेज़ में निर्धारित जोखिम भारों को लागू करने का विकल्प चुनने पर उनके इक्विटी से सम्बन्धित उधार (प्रावधानीकरण की दृष्टि से) निषेधात्मक रूप से मंहगे हो सकते हैं। इस प्रकार का कठोर जोखिम भार यह सुनिश्चित करने के लिए है कि बैंक इक्विटी के प्रति अपने ऋण जोखिम (exposure) में कमी लाएं तथा जमाराशियां स्वीकार करने और उधार देने के अपने मुख्य व्यवसाय पर ध्यान केन्द्रित करें। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इक्विटी के लिए जोखिम भारों की गणना करने हेतु दो दृष्टिकोण निर्धारित किए हैं, यथा- बाज़ार पर आधारित दृष्टिकोण और चूक की संभाव्यता / हानिकर चूक (PD / LGD) दृष्टिकोण। पहले

दृष्टिकोण का उपयोग करने वाले बैंकों को सूचीबद्ध इक्विटी के लिए 300 % का और "साधारण दृष्टिकोण" का उपयोग करने पर गैर-सूचीबद्ध इक्विटी के लिए 400% का जोखिम भार नियत करना होगा। पहले मॉडल (आंतरिक मॉडलों वाली पद्धति) रूपांतर सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध इक्विटी के लिए भार संघटक को घटा कर क्रमश: 300% और 200% पर ला देता है। चूक की संभाव्यता / हानिकर चूक वाला मॉडल निर्धारित किए जाने वाले जोखिम भार को इक्विटी एक्सपोजरों के मामले में 1,250 % पर स्थिर कर देता है। भारतीय बैंकों की इक्विटी व्यापार बही उनकी कुल निवेश बही का औसतन 5% से कम होती है।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

ऋण वृद्धि घट कर 18.5% हुई, जमाराशियां 17.25% बढ़ीं

उधार दरों में वृद्धि कारण बैंकं अग्रिमों की वृद्धि में गिरावट की प्रवृत्ति जारी रही। कारपोरेट ऋण के साथ खुदरा ऋणों में भी मंदी रही। भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के आंकड़ों के अनुसार 29 जुलाई के दिन ऋण वृद्धि वार्षिक आधार पर एक पखवाड़े पहले के 19.33 % से घट कर 18.5% के स्तर पर आ गई।

बैंकों को छोटे ऋणों से भारी लाभ की आशा

निधियों की बढ़ती लागत, मार्जिनों पर दबाव और बड़ी कम्पनियों द्वारा अधिकाधिक रूप से बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ECBs) का मार्ग अपनाए जाने को ध्यान में रखते हुए बैंक अपने उधार परिचालनों का मार्ग बदल रहे हैं। वे सूक्ष्म, लधु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को उधार देने पर अधिक बल दे रहे हैं। यद्यपि इस प्रकार के उधारों में अधिक जोखिम अपरिहार्य होता है, बैंक इस खण्ड के प्रति अपनी अनाश्रयता को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनसे अपेक्षाकृत अधिक मार्जिन प्राप्त होता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आकस्मिकताओं के लिए आरक्षित निधियां दो गुनी कीं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निरंतर बदतर होते यूरोपीय सॉवरेन संकट और मंद अमरीकी आर्थिक पुनरुत्थान के कारण वित्तीय अस्थिरता की आशंका के बीच इस वित्त वर्ष में आकस्मिकताओं के लिए अपनी आरक्षित निधियां बढ़ा कर दोगुने से भी अधिक कर दिया है। वित्तीय बाज़ार की कठिनाइयों ने पिछले वित्त वर्ष में भारतीय रिज़र्व बैंक के अंतरराष्ट्रीय लेनदेनों की लाभप्रदता घटा दी थी, क्योंकि अमरीकी और यू.के. जैसी सुरक्षित खज़ाना प्रतिभूतियों पर ब्याज दरं सर्वाधिक कम स्तर पर आ गई थीं। भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव वैश्विक वित्तीय बाज़ारों में संभाव्य अस्थिरता के प्रति चेतावनी देते रहे हैं, क्योंकि ग्रीक, पुर्तगाल और अन्य परिसरीय राष्ट्रों

को भारी सरकारी ऋणों के कारण निधियां जुटाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। स्टैंडर्ड एण्ड पुअर्स द्वारा अमेरिका की अधोमुखी रेटिंग ने आसन्न वैश्विक वित्तीय संकट में नये आयाम जोड़ दिए हैं। आकस्मिकताओं के लिए आरक्षित निधि हेतु किए गए प्रावधान एक वर्ष पहले के 5,168 करोड़ रुपये से बढ़ कर 12,167 करोड़ रुपये हो गए हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक की आय 12.73% बढ़ी

मुख्यत: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आरंभ किए गए चलनिधि प्रबन्धन परिचालनों के प्रभावों का निरूपण करते हुए वर्ष के दौरान उसके तुलनपत्र में महत्वपूर्ण रूप से विस्तार हुआ है। विदेशी आस्तियों से होने वाली आय में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है, जो अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में कम ब याज दरों का संकेत करती है। हालांकि, इस आय की घरेलू आस्तियों, जो विस्तृत हो गई हैं, से होने वाले अर्जनों से भरपाई कर ली गई है। वर्ष 2010-11 में विदेशी मुद्रा आस्तियों और सोने से 1.74% के स्तर वाले अर्जन की दर 2009-10 में दर्ज 2.09% के मुकाबले कम रही। जहां भारतीय रिज़र्व बैंक की सकल आय 12.73% बढ़ कर 2010-11 में 37,070.12 करोड़ रुपये हो गई, वहीं ग्रामीण व्यय में 3% वृद्धि हुई, जो 8,655.22 करोड़ रुपये हो गया। वर्ष 2010-11 के लिए सरकार को अंतरणीय अधिशेष की रकम 15,009 करोड़ रुपये थी। इसमें सरकारी पुरस्कारों, बिक्रीयोग्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याजगत अंतर की 1,322 करोड़ रुपये की रकम शा मिल थी। हालांकि, घरेलू स्रोतों से अर्जन में 8,138.84 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जो 2009-10 के 7,781.59 करोड़ रुपये से 104.59% की वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2010-11 में 15,920.43 करोड़ के स्तर पर पहुंच गया।

आधारभूत संरचना ऋणों में आस्ति-देयता असंतुलन जोखिम निहित होता है

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आधारभूत सुविधा क्षेत्र को दिया गया ऋण आस्ति-देयता असंतुलन (ALM) द्वारा बाधित होता है। आधारभूत सुविधा क्षेत्र को दिए गए बैंक ऋणों का अंश मार्च 2001 के अंत में 2.2% से बढ़ कर मार्च 2011 के अंत में लगभग 13.4% हो गया है। वैश्विक स्तर पर कारपोरेट बॉण्ड बाज़ार आधारभूत सुविधा विकास के वित्तीयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में कारपोरेट बॉण्ड बाज़ार अल्प विकसित है तथा सकल घरेलू उत्पाद के 2% के स्तर वाला सूचीबद्ध गैर सरकारी क्षेत्र के ऋणों का स्टॉक मलेसिया, को रिया और चीन जैसी उभरते बाज़ार वाली अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से कम है।

आधार दर प्रणाली नीतिगत दर में वृद्धियों के प्रति अधिक अनुकूल

पिछले दिनों पूर्ववर्ती न्यूनतम मूल उधार दर (BPLR) प्रणाली की तुलना में आधार दर नियत करने में बैंकों के बीच वृहत्तर अभिसरण देखने में आया है। भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2011-12 में बताया गया है कि इसके परिणामस्वरूप आधार दर प्रणाली को न्यूनतम मूल उधार दर प्रणाली की तुलना में नीतिगत दरों में वृद्धियों के प्रति अधिक अनुकूल पाया गया है। इसका संकेत सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा जुलाई 2010 से आधार दर में की गई औसत वृद्धि में मिलता है। नीतिगत दर में वृद्धि की गति प्रारंभ में धीमी थी, किन्तु उसमें दिसम्बर 2010-फरवरी 2011 के दौरान तेजी आ गई। इसके अलावा, इस अवधि में इन बैंकों द्वारा उनकी आधार दरों को बढ़ाने में लगाए जाने वाले दिनों की संख्या में कमी आ गई। हालांकि, खाद्येतर ऋण की वृद्धि में आई क्रमिक कमी के अनुसरण में पुनर्खरीद दर की तुलना में आधार दर में वृद्धि की गति फरवरी 2011 और उसके बाद से मंद हो गई। जबकि आधार दर को बढ़ाने में लगने वाले दिनों की संख्या भी बढ़ गई। बैंक भी आधार दरों को लागू किए जाने के पश्चात् भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की जाने वाली नीतिगत दरों में वृद्धि के प्रति अधिक अनुकूल हो गए हैं। इसके फलस्वरूप मौद्रिक नीति के प्रेषण का निर्धारण न्यूनतम मूल उधार दर प्रणाली की अपेक्षा नयी प्रणाली में सुदृढ़ हुआ है।

बासेल III वैश्विक भूमिका के लिए पर्याप्त नहीं

बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप (BCG) के एक अध्ययन के अनुसार वैश्विक मानको के समरूप बनने के लिए अधिक समर्थनकारी परिवेश की आवश्यकता है। बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप के भागीदार और निदेशक श्री सौरभ त्रिपाठी का कहना है कि बासेल III ही पर्याप्त नहीं है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जोखिम प्रबन्धन में उत्कृष्टता लाने के लिए एक केन्द्र का सृजन किए जाने की आवश्यकता है। उक्त अध्ययन में एक ऐसे विनियामक बदलाव की सिफारिश की गई है, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक बासेल III से आगे ााने के प्रतिमान निर्धारित करेगा। बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप की सिफारिशों में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए एक ाोखिम प्रबन्धन केन्द्रा का प्रायोान किए ााने, कम लागत वाले वित्तीय समावेशन की प्राप्ति के लिए मोबाइल प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित किए जाने तथा बैंकों द्वारा अनिवार्य रिपोर्टिंग में उत्पादकता मेट्रिकों को लागू किए जाने का समावेश है।

बैंक तीन माह वाले जमा प्रमाणपत्रों के पक्ष में

बैंकों द्वारा इस आशा के साथ कि आगे चल कर ब्याज दरों में कमी होगी, केवल अल्प अवधि के लिए उधार लेने को वरीयता दिए जाने के परिणामस्वरूप अल्पावधिक जमा प्रमाणपत्र (CD) बाज़ार में कूपनों में शूल परिलक्षित हुए हैं। इंडियन ओवरसीज़ बैंक के महा प्रबन्धक, खज़ाना श्री टी. एस. श्रीनिवासन का कहना है कि "बैंक अपेक्षाकृत लम्बी अवधि के लिए उधार लेने के बााय तीन माह की अवधि के लिए ामा प्रमाणपत्र ाारी कर रहे हैं, क्योंकि वे इस समय निधियों को

उच्चतर दरों पर अवरुद्ध नहीं करना चाहते।" चूंकि ऋण की मांग मंद है, बैंकों पर संसाधन जुटाने का दबाव अधिक नहीं है।

विनियामकों के कथन

चलनिधि को कमी वाले मोड में रखना आवश्यक, किन्तु आसान नहीं

भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री दीपक मोहन्ती के अनुसार प्रणालीगत चलनिधि को घटा कर रखना मौद्रिक नीति के प्रभावी प्रेषण के लिए एक चुनौती है। "हमारे अनुभवजन्य साक्ष्यों से यह पता चलता है कि परिचालनात्मक लक्ष्यों और अन्य अल्पावधिक बाज़ार की ब्याज दरों को नीतिगत संकेतों का प्रेषण कम चलनिधि वाली स्थितियों में सर्वाधिक प्रभावी होता है।" भारतीय रिज़र्व बैंक ने मई से एकल नीतिगत दर का मार्ग अपना लिया है। पिछले तीन माह के अनुभवों से यह पता चला है कि नयी कार्यविधि को कार्यान्वित किए जाने के बाद एक दिवसीय ब्‍याज दर अधिक स्थिर रही है।

वृद्धि और मुद्रास्फीति के बीच कोई समझौताकारी समन्वय नहीं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह संकेत दिया है कि अल्पावधिक रूप में कठोर मौद्रिक नीति के कारण आर्थिक विस्तार अपेक्षाकृत धीमा हो सकता है, किन्तु इन दोनों के बीच दीर्घावधिक समझौताकारी समन्वय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. सुबीर गोकर्ण का कहना है कि "दीर्घावधिक स्थिति से यह पता चलता है कि उच्च वृद्धि की स्थिर अवधि कम मुद्रास्फीति की स्थिर अवधि से विशिष्ट रूप से सह-सम्बन्धित होती है।" वे भारतीय रिज़र्व बैंक की आक्रामक दर वृद्धि का यह कहते हुए बचाव करते हैं कि रोक न लगाए जाने पर मुद्रास्फीति नियंत्रण से परे विस्तीर्ण हो गई होती। भारतीय रिज़र्व बैंक ने वृद्धि को बनाए रखने के स्थान पर मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने को प्राथमिकता दी है।

डालर ऋण जोखिमपूर्ण हैं

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के.सी. चक्रवर्ती ने भारतीय कम्पनियों को डालर में मूल्यवर्गित उधार राशियां उनसे जुड़े जोखिमों के कारण जुटाने से हतोत्साहित किया है। वे डालर के समक्ष रुपये की अस्थिरता पर भी चिंतित हैं। किसी भी कुशल बाज़ार में आप जिस मुद्रा को उधार लेते हैं वह आपकी निधि लागत को परिवर्तित नहीं करती। हालांकि, कुछेक मुद्राओं में लागत के कम होने पर जोखिम अधिक होते हैं। घरेलू ब्याज दरों में बारंबार वृद्धि और डालर के समक्ष रुपये के मूल्य में निरतर वृद्धि कम्पनियों को डालर में मूल्यवर्गित निधियां ुटाने हेतु

प्रोत्साहित करती लगती है। हम इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहित नहीं करते, क्योंकि सस्ते ऋण केवल अधिक ाोखिम आकर्षित करते हैं। ाोखिमों के प्रकटित होने पर कम्पनियां विफल हो ााती हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा बाज़ार में हस्तक्षेप नहीं करेगा

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. सुबीर गोकर्ण ने स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक का रुपये, जो अनिवार्यत: एक बाज़ार निर्धारित मुद्रा है, में उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है। इसके बजाय भारतीय रिज़र्व बैंक की तात्कालिक चिंता चलनिधि से सम्बन्धित है, क्योंकि "हम बाज़ार को चलनिधि की बाधा द्वारा व्यवधानित नहीं होने देना चाहते। वे दो कारक जो आगामी महीनों में हमारे दृष्टिकोण को तय करेंगे, घरेलू माग के दबाव और वस्तुओं के मूल्य हैं । मई-जून में जिंसों की कीमतों में थोड़ी कमी आई है। किन्तु हमारे द्वारा जुलाई की प्रक्रिया आरंभ किए जाने तक वे स्थिर हो गई थीं। अब यदि यह कमी वाली प्रवृत्ति की शुरूआत है, तो इसका हमारे दृष्टिकोण पर स्पष्ट रूप से कुछ प्रभाव होगा।"

गरीबों को वित्तीय सेवाओं की लागत अतिरिक्त रूप से अधिक है

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री आनंद सिन्हा के अनुसार गरीबों को वित्तीय सेवाओं की लेनदेन लागतें अल्प अवधि में उनकी राजस्व सृजन की तुलना में "अतिरिक्त रूप से अधिक" हैं। श्री सिन्हा का कहना है कि "मौजूदा बैंकिंग मॉडल अधिक लेनदेन लागतों जैसी चुनौतियों का पर्याप्त रूप से निराकरण करने में असमर्थ है। मांग पक्ष में भी वित्तीय निरक्षरता और उसके फलस्वरूप औपचारिक संस्थाओं से संपर्क करने के प्रति भय मौजूद है। शहरी जनसंख्या की कई एक कमतर आय वाली श्रेणियों सहित - वयस्क जनसंख्या का 50% से अधिक अब भी जिस रूप में वित्तीय सेवाओं की आपूर्ति संघटित है, उसके कारण वित्तीय क्षेत्र से अपवर्जित पड़ा है।"

विदेशी मुद्रा

विदेशी उधार 25% बढ़ कर जून में 3,33 बिलियन डालर हुए

विदेशी मुद्रा में उधारों से सम्बन्धित आंकड़ों के अनुसार ऐसा लगता है कि गृह बाज़ार में अधिक ब याज दरों को देखते हुए इंडिया इंक द्वारा विदेशी बाज़ारों का उपयोग अधिक आवृत्ति में किया जाने लगा है। बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ECBs) और विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय बॉण्डों (FCCBs) से सम्बन्धित आंकड़ों से इनके ं 25% की तीव्र वृद्धि के साथ 3.33 बिलियन अमरीकी डालर हो जाने का पता चला है। यह रकम कम्पनियों द्वारा मई में जुटाई गई 2.65 बिलियन डालर की कम से कहीं अधिक है। देशी बैंकर उन शीर्ष कम्पनियों के व्यवसाय को खो बैठने के प्रति चिंतित हैं,

जो अपनी आवश्यकताओं के लिए विदेशी बाज़ारों के उपयोग को वरीयता देंगे। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष श्री प्रतीप चौधरी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रमुख नीतिगत दरों को बढ़ा कर 8% किए जाने के बाद कहा है कि "इन दिनों कम्पनियां रुपये में मूल्यवर्गित ऋण नहीं चाहतीं। इसके बदले में वे गारंटी की मांग करती हैं, ताकि वे विदेशी बाज़ारों से तीन वर्षीय ऋण प्राप्त कर सकें।"[iv]

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि 621 मिलियन अमरीकी डालर घट कर 316 बिलियन अमरीकी डालर हुई

देश की विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि में लगातार दूसरे सप्ताह 621 मिलियन अमरीकी डालर की गिरावट हुई और वह 12 अगस्त को समाप्त सप्ताह के दौरान घट कर 316.605 बिलियन अमरीकी डालर रह गई। इसके पहले वाले सप्ताह में प्रारक्षित निधियों में 1.864 बिलियन अमरीकी डालर की गिरावट दर्ज हुई थी, जिससे वह घट कर 317.226 बिलियन अमरीकी डालर रह गई थी। यह गिरावट मुख्यत: मुद्रा के पुनर्मूल्यांकन के कारण आई है।

सितम्बर 2011 माह की विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) / अनिवासी विदेशी जमाराशियों की न्यूनतम दरें

अनिवासी विदेशी जमाराशियों की लिबोर / अदला-बदली (swap) दरें					
मुद्रा	लिबोर	अदला-बदली (swap)			
	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष		
अमरीकी डालर	0.79811	0.5100	0.6990		

अनिवासी विदेशी जमाराशियों की लिबोर / अदला-बदली (swap) दरें					
	लिबोर	अदला-बदली (swap)			
	लिबोर	अदला-बदली			
मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.79811	0.510	0.669	0.952	1.276
ाीबीपी	1.64719	1.2800	1.4400	1.6690	1.9030
यूरो	2.05375	1.539	1.708	1.910	2.132
ाापानी येन	0.55375	0.340	0.356	0.396	0.461
कनाडाई डालर	1.66000	1.157	1.317	1.514	1.724
आस्ट्रेलियाई डालर	5.43750	4.795	4.480	4.670	4.810

स्रोत : भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (FEDAI)

विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधियां

मद	19 अगस्त 2011 के दिन	19 अगस्त 2011 के दिन
	करोड़ रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
1	2	3
कुल प्रारक्षित निधियां	14 ,47, 725	318,,220
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	13, 01 ,030	285, 251
ख) सोना	1, 11, 940	25, 349
ग) विशेष आहरण अधिकार	21, 131	4, 633
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	13, 624	2, 987

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

बीमा

इर्डा ने बीमे में हित अंतरण कठिन किए

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) वित्तीय निवेशकों को ऐसे अल्पावधिक लाभों के लिए निवेशों, जिनसे दीर्घावधिक संभावनाएं प्रभावित हो सकती हैं, को प्रतिवर्तित करने से रोकने के लिए बीमा कम्पनियों के स्वामित्व एवं तनुकरण को नियंत्रित करना चाहता है। इसने किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपने हित (stake) को 5% से बढ़ाना चाहता हो और जो 1% अथवा उससे अधिक के हित खरीदने का इच्छुक हो, के लिए अनिवार्य पूर्वानुमोदन सहित उपायों की श्रृंखलाएं प्रस्तावित की हैं। इसके अतिरिक्त किसी बीमा कम्पनी के शेयरधारण के स्वरूप में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए विनियामक का सुस्पष्ट अनुमोदन आवश्यक होगा। शेयरधारकों के बीच अंतरण तथा नये इक्विटी निवेशों को कठोर बनाने के बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) के प्रयास बीमाकर्ताओं द्वारा प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों (IPOs) के नये नियमों की घोषणा किए जाने से पहले ही प्रारंभ हो गए हैं।

इर्डा ने आस्ति-देयता प्रबन्धन और दबाव परीक्षण के मानदंड तैयार किए

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने इक्विटी बाज़ार में गिरावट और ब्याज दर बाज़ार में उतार-चढ़ाव के समक्ष बीमा कम्पनियों की निवेश से सम्बन्धित गतिविधियों को सुरक्षित करने के

लिए आस्ति-देयता प्रबन्धन और दबाव परीक्षण की रूपरखा निर्धारित कर दी है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) का कहना है कि आस्ति-देयता प्रबन्धन उन बीमाकर्ताओं के वित्त के सुदृढ़ प्रबन्धन के लिए प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण है, जो अपनी भावी नकदी प्रवाह आवश्यकताओं और पूंजीगत अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए निवेश करते हैं। बीमा कम्पनियों को 45 दिनों के भीतर इसके पालन की पुष्टि करनी होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि निवेश से सम्बन्धित गतिविधियां तथा आस्ति की स्थितियां उनकी देयता, जोखिम प्रोफाइलों और उनकी शोधक्षमता की स्थितियों के अनुरूप हैं, बीमाकर्ताओं को उनकी आस्ति-देयता स्थितियों पर निगरानी रखने और उनका प्रबन्धन करने के लिए कार्यविधियों की व्यवस्था करनी होगी। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने बीमाकर्ताओं से इक्विटी मूल्यों में 30% की गिरावट होने और नियत ब्याज वाली प्रतिभूतियों में 100 आधार अंकों की गिरावट होने पर निवेशों के विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा है। इसके अलावा, बीमाकर्ताओं को मृत्यु दर, अस्वस्थता, खर्चों, आहरण, चूक की दरों में 10% के प्रतिकूल विचलन तथा नये कारबार के परिमाणों मे 25% की वृद्धि या कमी होने पर सूचित करना होगा। उन्हें निवेश करते समय इन कारकों के आधार पर परिदृश्य जोखिम को ध्यान में रखना होगा।

नयी नियुक्तियां

- श्री एम. भगवंतराव को स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्री सोनू भसीन को येस बैंक में शाखा बैंकिंग के ग्रुप प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्री ए.के. गुप्ता को केनरा बैंक के कार्यडालम निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

उत्पाद एवं गंठजोड़

संगठन	**जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ**	**उद्देश्य**
इंडसइंड बैंक	कैथेड्रल मॉडल ऑफ यूनाइटेड नेशन्स	एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें पाकिस्तान और नेपाल सहित उप महादवीप के विद्यालयीन बच्चों ने सहभागिता की। बैंक असामान्य शिक्षण के अनुभवों के माध्यम से ज्ञान प्रदान करने में दृढ़तापूर्वक विश्वास करता है।

केनरा बैंक	केनरा, एचएसबीसी ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी	उन स्मार्ट कार्डों पर सूक्ष्म बीमा उत्पाद प्रदान किए जाएंगे, जिन्हें वह अपनी वित्तीय समावेशन पहलकदमी में प्रदान करता है । बीमा 100 रुपये के प्रीमियम पर 22,500 रुपये की सुरक्षा उपलब्ध कराएगा।
कोटक महिन्द्रा बैंक	मलेसिया का सीआआईएमबी ग्रुप	उनके सम्बन्धित देशों में अनिवासी बैंकिंग और कारपरेट वित्त की सेवाएं प्रदान करना।
आईआईएफसीएल	आईडीबीआई	अंतरण वित्तपोषण एक ऐसी कार्यविधि है जिसके तहत बैंकों द्वारा आधारभूत सुविधा फर्मों को दिए हए ऋण अन्य संस्था को बेच दिए जाते हैं, ताकि बैंक अपनी अत्यावश्यक निधियों को ऋण करार के तहत भुगतान कार्यक्रम से काफी पहले वसूल कर सकें।

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (BIS)

"विज़न" के पिछले अंकों में हमने अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक के इतिहास, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (BCBS) , उसके गठन एवं संगठन के सम्बन्ध में सूचना प्रदान की थी तथा हाल के अंक में हमने मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक की भूमिका को वर्णित करने का प्रयास किया था। हमारी इच्छा है बैंकरों को अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक के अब तक अत्यधिक सुज्ञात नही तथ्यों से परिचित कराना। हम आशा करते हैं कि उपलब्ध कराई जा रही सूचना हमारे पाठकों की रुगि के अनुरूप ं है। हम अपने पाठकों से अपने प्रयासों के बारे में बहुमूल्य प्रति-सूाना आमंत्रित करते हैं।

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक के सम्बन्ध में सूाना उपलब्ध कराने के अपने प्रयासों को ाारी रखते हुए हम वर्तमान अंक में पिछले पांच वर्षों के दौरान वैश्विक वित्तीय संकटों की तुलना में अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक की पहलकदमियों की सूची प्रस्तुत कर रहे हैं:

वित्तीय संकट पर बासेल समिति की अनुक्रिया

8 जनवरी 2010	संयुक्त मंच द्वारा जारी वित्तीय विनियमन के विभेदीकृत स्वरूप और कार्य क्षेत्र की समीक्षा
11 जनवरी 2010	केन्द्रीय बैंकों के गवर्नरों और पर्यवेक्षण प्रमुखों के समूह ने बासेल समिति के सुधार पैकेज को पुनर्बलित किया।
22 जनवरी 2010	बासेल समिति ने प्रतिकर की प्रथाओं के निर्धारण की कार्यप्रणाली प्रकाशित की।

16 मार्च	बासेल समिति द्वारा कारपोरेट अभिशासन को बढ़ाने के सिद्धांत जारी किए गए।

2010	
18 मार्च 2010	सीमा-पार के बैंक निराकरण ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए सिफारिशें - बासेल समिति द्वारा जारी अंतिम दस्तावेज।
18 जून 2010	बासेल समिति द्वारा घोषित बासेल II बाज़ार जोखिम ढांचे में समायोजन।
16 जुलाई 2010	प्रति-चक्रीय पूंजी के सुरक्षित भंडार का प्रस्ताव -परामर्शी दस्तावेज़।
26 जुलाई 2010	केन्द्रीय बैंकों के गवर्नरों और पर्यवेक्षण प्रमुखों के बीच बासेल समिति के पूंजी एवं चलनिधि में सुधार के पैकेज पर व्यापक सहमति।
18 अगस्त 2010	अपेक्षाकृत अधिक पूंजी एवं चलनिधि की आवश्यकताओं के स्थूल-आर्थिक प्रभावों का निर्धारण।
12 सितम्बर 2010	केन्द्रीय बैंकों के गवर्नरों और पर्यवेक्षण प्रमुखों ने उच्चतर वैश्विक न्यूनतम पूंजी मानकों की घोषणा की।
4 अक्तूबर 2010	कारपोरेट अभिशासन को बढ़ाने के सिद्धांत - अंतिम दस्तावेज।
12 अक्तूबर 2010	पर्यवेक्षी मंडलों के सम्बन्ध में स्व्यवहार के सिद्धांत - अंतिम दस्तावेज।
14 अक्तूबर 2010	जोखिम और निष्पादन पारिश्रमिक के संरेखन की कार्यप्रणालियों की श्रेणी -परामर्शी दस्तावेज़।
19 अक्तूबर 2010	वित्तीय संकट पर बासेल समिति की अनुक्रिया- जी 20 की रिपोर्ट।
26 अक्तूबर 2010	न्यूनतम विनियामक पूंजी आवश्यकताओं तथा पूंजी के सुरक्षित भंडार का अंशांकन - एक टॉप-डाउन दृष्टिकोण ।
9 नवम्बर 2010	बासेल -III और वित्तीय स्थिरता।
17 दिसम्बर 2010	अधिक पूंजी और चलनिधि की आवश्यकताओं की दिशा में संक्रमण के स्थूल-आर्थिक प्रभाव का निर्धारण - अंतिम रिपोर्ट।
19 जुलाई 2010	प्रणालीगत महत्व वाले वैश्विक बैंक - मूल्यांकन की कार्यप्रणाली और अतिरिक्त हानि अवशोषण क्षमता सम्बन्धी आवश्यकता - परामर्शी दस्तावेज।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

नो कैश-आउट पुनर्वित्त

किसी मौजूदा बंधक का वर्तमान बकाया ऋण शेष जोड़िए अतिरिक्त ऋण निपटान लागत के बराबर या उससे कम रकम के लिए पुनर्वित्तीयन। यह मुख्यत: ऋण पर ब्याज दर के प्रभार को कम

करने और / अथवा बंधक की अवधि को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। नो कैश-आउट पुनर्वित्त को दर एवं अवधि पुनर्वित्त के रूप में भी जाना जाता है।

शब्दावली

चूक की संभाव्यता

चूक की संभाव्यता (PD) बासेल II के तहत बैंकिंग संस्था की किफायती पूंजी या विनियामक पूंजी की गणना करने हेतु प्रयुक्त होने वाली एक मापदंड होती है। यह बैंक के ग्राहक की एक विशेषता होती है। चूक की संभाव्यता (जिसे प्रत्याशित चूक की आवृत्ति भी कहा जाता है) एक ऐसी संभावना होती है कि ऋण की चुकौती नहीं की जाएगी और वह चूक में परिणत हो जाएगा। चूक की संभाव्यता की गणना ऐसे प्रत्येक ग्राहक, जिसने (थोक बैंकिंग के मामले में) ऋण ले रखा है अथवा (खुदरा बैंकिंग के मामले में) इसी प्रकार की विशेषताओं वाले ग्राहकों के पोर्टफोलियों के मामले में की जाती है। चूक की संभाव्यता की गणना करने के लिए प्रतिपक्ष / पोर्टफोलियो के ऋण इ तिवृत्त और निवेश की प्रकृति को ध्यान में रखा जाता है।

हानिकर चूक

हानिकर चूक अथवा एलजीडी जोखिम मॉडलों में एक सामान्य मापदंड होती है तथा वह बासेल II के तहत बैंकिंग संस्था के मामले में किफायती पूंजी या विनियामक पूंजी की गणना करने के लिए भी प्रयुक्त होने वाली एक मापदंड होती है। यह बैंक के ग्राहक के सम्बन्ध में किसी भी अनाश्रयता (exposure) की एक विशेषता होती है। अनाश्रयता (exposure) वह रकम होती है जिसकी किसी निवेश में हानि हो सकती है।

संस्थान की गतिविधियां

लीडरशिप सेन्टर, आईआईबीएफ, कुर्ला में प्रशिक्षण की गतिविधियां

- संस्थान द्वारा 20 अगस्त 2011 को सूना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा पर एक अर्ध-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बैंकिंग उद्योग के 15 वरिष्ठ सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारियों ने भाग लिया।

- संस्थान ने आस्ट्रेलियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वेस्टर्न आस्ट्रेलिया के सहयोग से 29 अगस्त, 2011 से 3 सितम्बर 2011 तक एक के बाद दूसरे दो 3 दिवसीय नेतृत्व विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया। प्रत्येक कार्यक्रम में 23 सहभागियों ने सहभागिता की।

- टॉपसिम - सर्वव्यापी बैंकिंग : संस्थान ने टाटा इंटरऐक्टिव सिस्टम के सहयोग से 20 और 21 अक्तूबर 2011 को टॉपसिम - सर्वव्यापी बैंकिंग पर एक द्विदिवसीय कार्यक्रम की घोषणा की है। विस्तृत जानकारी के लिए www.iibf.org.in. देखें।

संस्थान समाचार

5वां आर.के. तलवार अनुस्मारक व्याख्यान

"भारत में वित्त का भविष्य" पर 5वां आर.के. तलवार अनुस्मारक व्याख्यान 07-09-2011 को आईसीआईसीआई बैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री एन. वाघुल द्वारा भारतीय स्टेट बैंक सभागृह, नरीमन प्वाइंट में दिया गया। उक्त व्याख्यान www.iibf.org.in. पर उपलब्ध है।

वेबेक्स कक्षाएं : संस्थान जेएआईआईबी / डीबी एण्ड एफ / सीएआईआईबी के अभ्य र्थियों के लिए वेब कक्षाओं का आयोजन कर रहा है। सत्रों में प्रवेश की अनुमति ऐसे सभी अभ्यर्थियों को दी जाएगी, जिन्होंने नवम्बर / दिसम्बर 2011 की परिक्षाओं के लिए पंजीकरण करा रखे हैं। विस्तृत जानकारी के लिए www.iibf.org.in. देखें।

हीरक जयंती और सी.एच. भाभा बैंकिंग ओवरसीज रिसर्च फेलोशिप

संस्थान वर्ष 2011-12 के लिए हीरक जयंती और सी.एच. भाभा बैंकिंग ओवरसीज रिसर्च फेलोशिप के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करता है। विस्तृत जानकारी के लिए www.iibf.org.in. दे खें।

- भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / दक्षिण -42 / 2010 -12
- मुंबई पत्रिका चैनल छंटाई कार्यालय मुंबई - 1 पर प्रत्येक महीने की 25वीं और 28वीं तारीख को प्रेषितकरें।

छद्म परीक्षा

संस्थान जेएआईआईबी / डीबी एण्ड एफ / सीएआईआईबी के अभ्यर्थियों के लिए 1 अक्तूबर 2011 से छद्म परीक्षा की सुविधा उपलब्ध कराएगा। विस्तृत जानकारी के लिए www.iibf.org.in. देखें।

परियोजना वित्त

संस्थान आईएफएमआर, चेन्नै के सहयोग से परियोजना वित्त में 16वें प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का आयोजन कर रहा है। बैच के लिए कैम्पस प्रशिक्षण 21 नवम्बर से 26 नवम्बर 2011 तक आयोजित होगा। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

संपर्क कक्षाएं

आंचलिक कार्यालयों द्वारा आगामी जेएआईआईबी / सीएआईआईबी परीक्षाओं के लिए संपर्क कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

आईआईबीएफ की परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री

संस्थान ने विविध परक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर प रिपत्रों से एकत्रित अतिरिक्त अध्ययन सामग्री अपने पोर्टल पर डाल रखी है (अधिक जानकारी के ि लए साइट www.iibf.org.in देखें)।

बाज़ार की खबरें

भारित औसत मांग दरें

8.20
8.00
7.80
7.60
6.40
7.20
01/08/11 02/08/11 04/08/11 08/08/11 10/08/11 11/08/11 20/08/11 23/08/11 25/87/11 26/08/11 29/08/11

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, जुलाई, 2011

- माह के दौरान मांग दरें पुनर्खरीद (रेपो) दरों अर्थात 8% के आसपास मंडराती रहीं।
- 8% पर पहुंची मांग दरें अनिरुद्ध बाज़ार का संकेत देते हुए 7.45% के न्यून स्तर तक पहुंा गईं,।
- बाज़ार अधिक अस्थिरता के बिना श्रेणीबद्ध बना रहा।

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

77
72
67
62
57
52
47
42
01/08/11 04/08/11 08/08/11 10/08/11 11/08/11 16/08/11 18/08/11 19/08/11 22/08/11 25/08/11 29/08/11 30/08/11
अमरीकी डालर यूरो 100 जापानी येन पौंड स्टर्लिंग

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

- रुपया 44.5450 / 5550 प्रति डालर पर बंद हुआ, जो 3री को उसके 44.31 / 32 पर बंद होने के स्तर से कमजोर रहा।
- पहले सप्ताह के अंत में रुपया 5 सप्ताह के कमतर स्तर पर पहुंा गया, प्रतिफल गिर गया।
- 8वीं को केन्द्रीय बैंक के यह कहने पर कि स्टैंडर्ड एण्ड पुअर्स द्वारा अमरीकी ऋणों के क्षेणी निर्धारण में कमी के पश्चात् वृद्धि के प्रति अधोमुखी ाोखिमों में वृद्धि हुई होगी, रुपया 6 ाह में अपने न्यूनतम स्तर तक लुका गया।
- माह के मध्य में व्यापार के दौरान 45.4625 के न्यूनतम स्तर तक कमजोर पड़ने के बाद 45.4050 / 4150 प्रति डालर पर बंद हुआ।
- माह के दौरान रुपया डालर के समक्ष 4% की गिरावट दर्ज करते हुए लगभग सभी प्रमुख मुद्राओं के समक्ष कमाोर पड़ गया।
- रुपया यूरो के समक्ष 5.90% कमाोर पड़ा।
- रुपये में ाापानी येन और स्टर्लिंग पौंड के समक्ष क्रमश: 4.94% और 4.62% की गिरावट आई।

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

18500
18000
17500
17000
16500
16000
15500

02/08/11 04/08/11 05/08/11 09/08/11 10/08/11 12/08/11 18/08/11 19/08/11
23/08/11 25/08/11 26/08/11 29/08/11

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

डॉ. आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, डॉ. आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।

संपादक : डॉ. आर. भास्करन

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.